



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2018/ फाल्गुन 7, 1939

No. 72]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2018/ PHALGUNA 7, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
(जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना)
नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2018
(निर्णयिक समीक्षा)
(मामला सं. 02/2018)

विषय - चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "मेटा-फिनाइलीन डायमीन" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा की शुरूआत

फा.सं. 7/2/2018-डीजीएडी (मामला सं. एसएसआर 02/2018):—1995 में और उसके बाद यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिधारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेटा-फिनाइलीन डायमीन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

2. यतः संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जाँच चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु आयातों पर प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 14/4/2012-डीजीएडी दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा शुरू की गई थी। अधिसूचना सं. 02/2013-सीमाशुल्क दिनांक 22 मार्च, 2013 द्वारा अनंतिम शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 14/4/2012-डीजीएडी दिनांक 17 दिसंबर, 2013 के माध्यम से अंतिम जाँच परिणाम प्रकाशित किए गए और वित्त मंत्रालय द्वारा 1076 GI/2018

अधिसूचना सं. 11/2014-सीमाशुल्क, दिनांक 11 मार्च, 2014 के द्वारा चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधीशुल्क लगाया गया था।

3. विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग की ओर से मै. आरटी इंडस्ट्रीज लि. (जिसे आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर प्राधिकारी ने याचिका को 1995 में और उसके बाद यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार पाया है।

ख. निर्णयिक समीक्षा की शुरूआत

4. दायर याचिका के अनुपालन में, निर्दिष्ट प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 के (5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्षों के बाद निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 के (5) के अनुसार निर्णयिक समीक्षा जाँच की शुरूआत करते हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. विचाराधीन उत्पाद मेटा-फिनाइलीन डायमीन है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के उपशीर्ष 2921 5120 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

6. चूंकि प्रस्तावित जाँच एक निर्णयिक समीक्षा जाँच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा पूर्व में समाप्त हुई मूल जाँच के समान ही है।

घ. प्रक्रिया

7. इस जाँच से यह निर्धारित होगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है। प्राधिकारी जाँच करेंगे कि क्या पाटन और कारणात्मक क्षति को समाप्त करने के लिए शुल्क लागू करना आवश्यक है।

- इस समीक्षा जाँच में शामिल देश चीन जन. गण. है।
- वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 अक्टूबर, 2016 से 30 सितंबर, 2017 तक की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2014- मार्च 2015, अप्रैल 2015 – मार्च 2016, अप्रैल 2016 – मार्च 2017 और जाँच अवधि शामिल है।
- संबंधित नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय, संबद्ध देश में उत्पादक/निर्यातक को विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की विक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में बाजार दशाओं की मौजूदगी को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित के संबंध में स्पष्ट कर सकते हैं और पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा सकते हैं:

- कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, विक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।

- उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।

ग. उत्पादक/नियांतक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।
 घ. विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

ड. सूचना प्रस्तुत करना

8. संबद्ध देश में ज्ञात नियांतकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है:

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

9. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

च. समय-सीमा

10. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजा जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

11. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

छ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

12. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (घ). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनकी साफ्ट प्रतियां होनी चाहिए।

13. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

14. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

15. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

16. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

17. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशेष प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ज. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

18. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साध्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

झ. असहयोग

19. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2018

(Sunset Review)

(Case No. SSR 02/2018)

Subject: Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed on imports of Metaphenylene Diamine originating in or exported from China PR.

F. No. 7/2/2018-DGAD (Case No. SSR 02/2018).— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) recommended imposition of anti -dumping duty on imports of “Metaphenylene Diamine” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR.(hereinafter referred to as the subject country).

2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. *vide* Notification No. – 14/4/2012-DGAD, dated 19th June, 2012 on imports of subject goods from China PR. Provisional duties were imposed *vide* Notification No. 02/2013-Customs dated 22nd March, 2013. The final finding was published by the Authority *vide* Notification No. 14/4/2012-DGAD, dated the 17th December, 2013 and Ministry of Finance imposed definitive anti-dumping duty *vide* Notification No. 11/2014-Customs, dated 11th March, 2014 on all imports of subject goods originating in or exported from China PR.

3. Based on the petition filed by M/s Aarti Industries Ltd (*hereinafter referred to as Petitioner*), on behalf of the domestic industry for the product under consideration, the Authority finds the petition in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff

(Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules)

B. Initiation of Sunset Review

4. Pursuant to the petition filed, the Designated Authority in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, hereby initiates sunset review in accordance with section 9A(5) of the Custom Tariff(Amendment) Act read with Rule 23 of Antidumping Rules.

C. Product under Consideration and Like Article

5. The product under consideration in the present investigation is “Meta Phenylene Diamine”. The product is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under Customs Sub-heading No. 29215120. However, customs classification is indicative in nature and not binding on the scope of the investigation.

6. Since the proposed investigation is a sunset review investigation, the scope of the product under consideration is the same as that of the previously concluded original investigation.

D. Procedure

7. The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether imposition of the duties is necessary to offset dumping and causing injury.

- i. The country involved in this review investigation is China PR.
- ii. The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st October, 2016 to 30th September, 2017. The injury investigation period will however cover the periods April'2014-March'15, April'2015– March'2016, April'2016-March'2017 and the POI.
- iii. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

While submitting questionnaire response, producer/ exporter may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production and sale of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:

- (a) Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labor, output, sales and investment, are made in response to market signal reflecting supply and demand and without significant state interference and weather cost of major inputs substantially reflect market value.
- (b) Production costs and financial situation does not suffer from any distortion.
- (c) The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
- (d) Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

E. Submission of Information

8. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India

Ministry of Commerce and Industry

Department of Commerce

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties

4th Floor, Jeevan Tara Building

5, Parliament Street, New Delhi – 110001

9. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

F. Time Limit

10. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

11. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

G. Submission of information on confidential basis.

12. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a)marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.

13. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

14. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

15. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

16. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

17. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

H. Inspection of public file

18. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

I. Non-cooperation

19. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority